वर्ष 2019-20 में निजी कॉर्पोरेट निवेश : सुधार के आसार[*]

इस आलेख में 2018-19 और 2019-20 के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा भारत में निवेश की संभावनाओं से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है और वित्तपोषण के अलग-अलग माध्यमों में पहले से स्वीकृत / अनुबंधित परियोजनाओं में वर्ष 2019-20 के लिए परिकल्पित पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के आधार पर सुधार के संकेत लक्षित किए गए हैं। वित्तपोषण के प्रमुख चैनलों के माध्यम से स्वीकृत / अनुबंधित परियोजनाओं की कुल लागत (मूल्य के आधार पर) से निवेश गतिविधि की निकट भविष्य में रहने वाली दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है और वर्तमान में अर्थव्यवस्था में निजी निवेश की कमजोर मांग के वातावरण में, यह लेख निवेश चक्र में आमूलचूल बदलाव की शुरुआत की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है।

भूमिका

आर्थिक विकास निजी निवेश पर टिका होता है। विकास से जुड़े साहित्य में, निवेश को विकास के प्राथमिक वाहकों में से एक माना गया है। निवेश जीडीपी का प्रमुख घटक होता है और इस रूप में वह निवेश, श्रम उत्पादकता, क्षमता निर्माण, नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत, रोजगार सृजन आदि को भी प्रभावित कर सकता है और इसीलिए इससे भावी विकास परिदृश्य के शुरुआती संकेत मिल सकते हैं। इस प्रकार, लघु-से मध्यम अवधि तक के आर्थिक विश्लेषण और पूर्वानुमान के उद्देश्यों से, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की समय पर जानकारी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि, कंपनियों के प्रकाशित वार्षिक लेखा से निजी निवेश संबंधी वास्तविक (हार्ड) आंकड़े काफी देर से मिलते हैं, इसलिए वे अल्पकालिक विश्लेषण के लिए बहुत उपयोगी नहीं हो सकते। यही कारण है कि कंपनियाँ परिकल्पित कॉर्पोरेट निवेश संबंधी जानकारी जुटाने के लिए सर्वे आधारित तरीकों को उपयोग में लाती हैं (एबर्गर, 2005; औरिज़ियो और स्टेफानो, 2011; बार्न्स एंड एलिस, 2005; फेरारी, 2005; ओस्टरहोम, 2013)। सर्वेक्षण-आधारित परिणाम वर्तमान निवेश के स्वरूप और निवेश के इरादों, जिनके निकट भविष्य में मूर्त रूप लेने की संभावना है, दोनों के आकलन के लिए बहुमूल्य साधन उपलब्ध कराते हैं।

अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हुए, 1980 के दशक के उत्तरार्ध से ही निवेश के इरादों के आकलन और पूर्वानुमान के लिए भारत में सर्वेक्षण कराने की दिशा में प्रयास तेज किए गए हैं। 1970 के दशक से, भारतीय रिज़र्व बैंक निजी कंपनियों के क्षेत्र की कैपेक्स योजनाओं (जो पहले से ही वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित हैं) पर नज़र रख रहा है, ताकि रंगराजन (1970) द्वारा अपनाई गई कैपेक्स के समयबद्ध चरणों वाली प्रणाली के आधार पर निवेश के इरादों से जुड़े परिदृश्य को समझा जा सके। इस तरह के लेख शुरू में इकोनॉमिक एण्ड पॉलीटिकल वीकली और इसके बाद (1989 से) आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित किए गए थे।

निवेश के इरादों संबंधी डेटा का प्राथमिक स्रोत कैपेक्स प्रोजेक्ट्स को वित्तपोषण प्रदान करने वाले जैसे, बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय संस्थान (एफआई)[1] के साथ-साथ बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)[2], विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (एफसीसी), रुपये में मूल्यवर्गित बॉन्ड (आरडीबी) और आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), फॉलो-ऑन पब्लिक पेशकश (एफपीओ) और एक वर्ष के लिए अधिकार निर्गम थे।

इस लेख में 2018-19 और 2019-20 के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी योजनाओं के आधार पर निवेश के उनके इरादों पर चर्चा की गयी है। लेख को छह भागों में बांटकर तैयार किया गया है। भाग II इसकी कार्यपद्धति और उसकी सीमाओं पर चर्चा करता है। भाग III समीक्षाधीन अवधि में स्वीकृत या अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताओं, उनके वित्तपोषण, क्षेत्र और उद्योग-वार उनके वितरण जैसे पहलुओं को रेखांकित करता है। भाग IV स्वीकृत / अनुबंधित ऋण / वित्तपोषण के चरणबद्ध प्रोफाइल से संबंधित है और कॉर्पोरेट निवेश की वृद्धि का अनुमान लगाता है। भाग V वर्ष के दौरान किए गए निजी स्थानन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का

---

[*] यह आलेख सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग के कॉर्पोरेट अध्ययन प्रभाग की प्रोणिता पी. साइकियाऔर आर. के. सिन्हा ने तैयार किया है। इसमें व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं और ये भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस विषय पर इससे पहले का अध्ययन भारतीय रिज़र्व बैंक के मासिक बुलेटिन के मार्च 2019 अंक में 'वर्ष 2018-19 में 'निजी कॉर्पोरेट निवेश : धीमी वसूली जारी' शीर्षक से प्रकाशित हुआ था।

[1] इसमें सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक, प्रमुख निजी और विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल किए गए हैं जो कि परियोजनाओं के वित्तपोषण में सक्रियता से लगे हुए हैं यथा, भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम (आईएफसीआई), जीवन बीमा निगम (एलआईसी), पावर फाइनांस कॉर्पोरेशन (पीएफसी), भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम)।

[2] ईसीबी में रुपये में मूल्यवर्गित बॉण्ड (आरडीबी) शामिल हैं।

विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भाग VI में अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

II. क्रियाविधि

वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तपोषित कॉरपोरेट परियोजनाओं का समय के अलग-अलग चरणों के आधार पर अल्पकालिक पूर्वानुमान (एक वर्ष आगे का) लगाने की पद्धति का श्रीगणेश 1970 में डॉ. सी. रंगराजन द्वारा किया गया था। इस पद्धति के तहत कैपेक्स के आकलन के लिए, स्वीकृत परियोजनाओं के डेटा बैंकों / एफआई से प्राप्त किए जाते हैं जिसमें ईसीबी/ एफसीसीबी/ आईपीओ/ एफपीओ/ अधिकार निर्गमों जैसे अन्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त वित्तपोषण के आंकड़े पूरक का कार्य करते हैं। मूल्यांकन के समय कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्याशित फ़ेजिंग प्लान के आधार पर, वर्ष के दौरान संभावित कैपेक्स के स्तर का एक अनुमान प्राप्त होता है।

इस विश्लेषण में, भारतीय रिज़र्व बैंक में आंतरिक रूप से उपलब्ध जानकारी और साथ ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करने का समुचित प्रयास किया गया है कि प्रत्येक परियोजना के केवल एक सेट की प्रविष्टि की जाए भले ही वह कई माध्यमों से वित्तपोषित हो। उन परियोजनाओं को शामिल नहीं किया गया है जो इनमें से किसी भी माध्यम से वित्तपोषित नहीं हैं या जो ₹10 करोड़ से कम लागत वाली हैं। 51 प्रतिशत से कम निजी स्वामित्व वाली परियोजनाएं जो न्यासों, केंद्र और राज्य सरकारों की उपक्रम हैं और शैक्षणिक संस्थानों को भी इस अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है।

ये अनुमान इस धारणा के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं कि कंपनियां अपने प्रत्याशिक खर्च की योजनाओं के अनुसार चलती हैं। हालाँकि, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली के मामले में ये अनुमान राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एन ए एस) में उपलब्ध कॉर्पोरेट निश्चित निवेश के प्रत्याशित अनुमानों से थोड़ा भिन्न हो जाते हैं क्योंकि कुछ प्रत्याशित पूर्वानुमान राशि एवं निवेश के समय कीदृष्टि से वास्तविक निवेश में नहीं परिणत हो पाते।

III. स्वीकृत / अनुबंधित परियोजनाओं की विशेषताएँ

वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंकों और एफआई ने ₹1,76,581 करोड़ की कुल लागत वाले निजी कंपनियों के 414 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी। 535 कंपनियां ऐसी हैं, जिन्होंने बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से किसी भी वित्तपोषण का लाभ नहीं उठाया, लेकिन ईसीबी / एफसीसीबी के साथ उन्होंने ₹76,515 करोड़ की ऋण राशि का अनुबंध किया। इसी तरह, 39 कंपनियों ने किसी भी बैंक वित्त या ईसीबी / एफसीसीबी का लाभ नहीं उठाया, लेकिन घरेलू इक्विटी निर्गमों के ज़रिए अपनी कैपेक्स जरूरतों के लिए ₹609 करोड़ जुटाए। कुल मिलाकर, 988 परियोजनाओं की निवेश योजनाएं 2018-19 के दौरान तैयार की गयीं जिनकी कुल राशि ₹2,53,705 करोड़ थी, जबकि वर्ष 2017-18 में 955 परियोजनाओं के तहत कुल निवेश ₹2,07,673 करोड़ था (अनुबंध: सारणी ए1-ए4)।

परियोजनाओं के आकार-वार वितरण से यह पता चलता है कि किसी विशिष्ट समयावधि में स्वीकृत अलग-अलग परियोजनाओं की लागत का वितरण किस प्रकार होता है। अनुभवजन्य परिणामों से पता चलता है कि परियोजना लागत के सांख्यिकीय वितरण एक भारी राइट टेल होता है। किसी अवधि में मंजूर परियोजनाओं की औसत लागत इस टेल की प्रकृति और प्रोफ़ाइल से प्रेरित होती है जो आउटलाइयर्स (बड़े मूल्यों) की सापेक्ष उपस्थिति को दर्शाती है। परियोजनाओं के आकार-वार वितरण ने 2017-18 की 3 मेगा परियोजनाओं (₹5,000 करोड़ और उससे अधिक की) की संख्या की तुलना में 2018-19 में कुल 5 मेगा परियोजनाओं तथा कुल परियोजना लागत में उनकी हिस्सेदारी में वृद्धि भी दर्शायी। वर्ष 2018-19 में कुल परियोजना लागत में हुई वृद्धि में भी इसका आंशिक योगदान रहा, अन्यथा 2017-18 की तुलना में 2018-19 में कुल परियोजनाओं की संख्या में गिरावट देखी गयी। मेगा परियोजनाएं आम तौर पर लंबे समय तक चलती हैं, जैसा कि उनकी चरणबद्ध योजना में परिलक्षित होता है, और ऐसी परियोजनाओं की उपस्थिति से वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत बढ़ती है। बड़े आकार वाली -₹1,000 करोड़ से ₹5,000 करोड़ तक की - लगभग 41 परियोजनाएं थीं जिनकी हिस्सेदारी कुल परियोजना लागत की लगभग 41 प्रतिशत थी (बॉक्स 1 और अनुबंध: सारणी ए5) ।

परियोजनाओं के उद्देश्य-वार पैटर्न पर दृष्टिपात करने पर यह पता चलता है कि 2018-19 के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में सबसे बड़ी हिस्सेदारी (76.9 प्रतिशत) हरित क्षेत्र (नई) परियोजनाओं में निवेश की थी, और इसके बाद मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण का रहा जिसकी हिस्सेदारी कुल परियोजना लागत का 19.7 प्रतिशत थी, जो कि 2017-18 की इसकी हिस्सेदारी में अधिक है (अनुबंध: सारणी ए6)।

बॉक्स 1: परियोजना लागत का सांख्यिकीय वितरण

किसी विशेष समय अवधि में स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत संयुक्त रूप से परियोजनाओं की संख्या और प्रत्येक परियोजना की राशि से प्रभावित होती है। जैसाकि पहले खंड में इंगित किया गया है, 10 करोड़ रूपये और उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाएं ही केवल संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट की जाती हैं, और इसलिए बहुत छोटी परियोजनाओं (10 करोड़ से कम वाली) की जानकारी डेटासेट में कैप्चर नहीं की जाती है।

प्रोफ़ाइल (आकार के संदर्भ में) का अध्ययन करने के लिए, 5 साल की अवधि (2014-15 से 2018-19) के दौरान बैंकों / एफआई द्वारा अनुमोदित सभी 2,112 परियोजनाओं के सेट पर विचार किया गया। परिणामों से पता चलता है कि परियोजना लागत का सांख्यिकीय वितरण अत्यधिक असमान (विषम) है जिसमें एक भारी (मोटी) राइट टेल है और जिनका समांतर माध्य ₹332.91 करोड़ है, जो इसके 75वें प्रतिशत से बड़ा है। वितरण से पता चलता है कि लगभग 30 प्रतिशत परियोजनाओं की लागत ₹10 करोड़ से ₹30 करोड़ की बीच थी। अंतिम 5 प्रतिशत का अवलोकन करने से पता चलता है कि ये ₹1,480 करोड़ से ₹15,000 करोड़ की व्यापक रेंज में हैं, जो परियोजनाओं के कम बारंबारता और उनके विभिन्न आकार को दर्शाते हैं (सारणी बी1 और चार्ट बी 1)।

परियोजना लागत के डेटासेट के वितरण की फिटिंग से यह बात सामने आयी है कि 3-पैरामीटर लॉगनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उचित तरीके से डेटासेट का वर्णन करता है। 3-पैरामीटर लॉगनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की संभाव्यता घनत्व फलन को इस रूप में परिभाषित किया गया है:

$$f(x) = \exp[-1/2\{\ln(x-\gamma) - \mu\}^2/\sigma] / (x-\gamma)\,\sigma\sqrt{2\pi}$$

सारणी बी1 : परियोजना लागत आकार की विवरणात्मक सांख्यिकी

परियोजनाओं की संख्या	2112	25वीं प्रतिशतता ($ति_1$)	24.43
माध्य	332.91	माध्यिका ($ति_2$)	69.04
मानक विचलन	880.64	75वीं प्रतिशतता ($ति_3$)	278.72
न्यूनतम	10.00	95वीं प्रतिशतता	1480.00
अधिकतम	15000.00	स्क्यूनेस	7.93
रेंज	14990.00	कर्टोसिस	94.66

जहां, γ, μ और σ वितरण के तीन मानदंड हैं। वितरण पारंपरिक 2-पैरामीटर लॉगनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ γ=0में परिवर्तित हो जाता है।

अनुमानित मानदंड के साथ लॉगनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुमानित मानदंड परियोजना लागत की रूपरेखा का आकलन करने और विभिन्न प्रासंगिक संभावनाओं (उदाहरण : इसकी संभावना कि एक किसी विशेष परियोजना की लागत एक विशेष बैंड के अंतर्गत आएगी) की गणना करने में उपयोगी हो सकते हैं। तीन परीक्षण आँकड़े अर्थात, कोलमोगोरोव-स्मिरनोव, एंडरसन-डार्लिंग और ची-स्क्वायर परियोजनाओं की लागत के वितरण की प्रकृति का वर्णन करने में लॉगनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की उपयुक्तता की पुष्टि करते हैं (सारणी बी2)। इसके अलावा, संभाव्यता -संभाव्यता (पीपी) प्लॉट, 45° के कोण पर एक सीधी रेखा को दशार्ती है जो परियोजना लागत (चार्ट बी 2) के वितरण की लॉग- नॉर्मेलिटी की पुन: पुष्टि करता है।

इसके अलावा, उक्त वितरण की उपयुक्तता को पहचानने और स्थापित करने के लिए, इस डेटासेट के सबसेट का वर्णन करने के लिए मापदंडों

चार्ट बी 1: परियोजना लागत का फिटेड वितरण

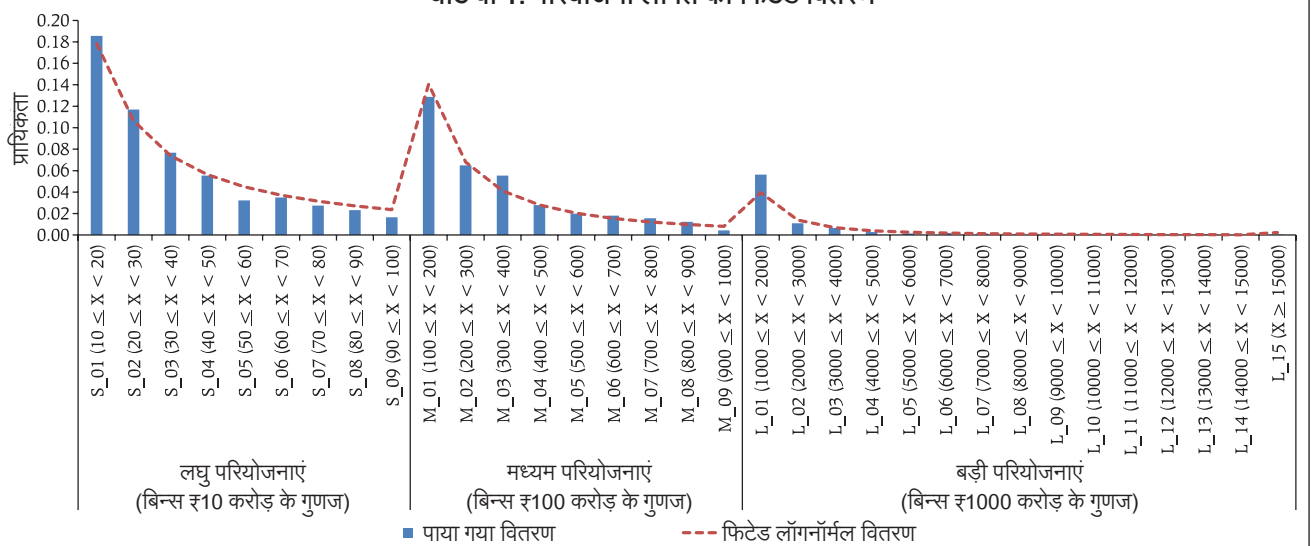

टिप्पणी : परियोजनाओं कीलागत को तीन श्रेणियों में बांटा गया था, यथा, छोटी (₹10 करोड़ से लेकर ₹100 करोड़ से कम वाली), मध्यम (₹100 करोड़ से लेकर ₹1000 करोड़ से कम वाली) और बड़ी (₹1000 करोड़ से अधिक वाली)। यह वितरण मल्टी-मोड वाला नहीं है जैसा कि अलग-अलग बिन आकारों के कारण बाहर से लग सकता है। बिन आकारों का समुचित चयन इस प्रकार किया गया था ताकि राइट टेल निश्चित रूप से दिखायी पड़े।

(क्रमश:...)

सारणी बी2 : मानकों के आकलन और फिट की अच्छाई के लिए परीक्षण सांख्यिकी

मानकों के आकलन		परीक्षण सांख्यिकी	
γ	9.9083	कॉल्मोगोरोव-स्मरनोव (के एस)	0.029
μ	4.1071	एन्डडर्सन-डार्लिंग (एडी)	2.799
σ	1.9516	ची-स्क्वायर	39.665

टिप्पणी : कॉल्मोगोरोव-स्मरनोव (के एस), एन्डडर्सन-डार्लिंग (एडी) और ची-स्क्वायर परीक्षण फिट की अच्छाई की जाँच के लिए किए जाते हैं *अर्थात* चयनित सैद्धांतिक वितरण कितनी अच्छी तरह इसके मूलभूत डेटासेट में फिट होता है।

का आकलन वांछनीय है, जिसके समरूप होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, 3-पैरामीटर लॉगनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को दो डेटा सबसेट में रखा गया था – स्थान के अनुसार विभाजन (अर्थात, एकल-राज्य और बहु-राज्य)। फिटिंग और अनुमानित मानदंड स्थान के आधार पर परियोजनाओं की विशेषताओं में अंतर को दर्शाते हैं। बहु-राज्य परियोजनाओं में परियोजना लागत का औसत आकार एकल-राज्य परियोजनाओं की तुलना में अधिक था। हालांकि, पहले वाले कम असमान और कम लेप्टोक्यूरेटिक (बढ़े हुए) पाए जाते हैं।

गैर-बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के सापेक्ष बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के प्रोफाइल का विश्लेषण बताता है कि बिजली, सड़कों और हवाई अड्डों के नेतृत्व में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं का हिस्सा मोटे तौर पर लगभग 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत (सीमा के भीतर) रहा है राशि), हालाँकि परियोजनाओं की संख्या के संदर्भ में इनकी हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत है। अनुमानित

चार्ट बी 2 : पीपी प्लॉट

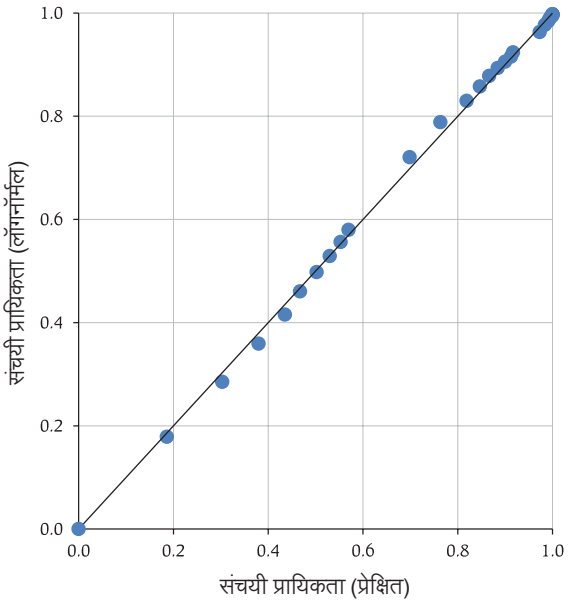

लॉगनॉर्मल वितरण का उपयोग करके बुनियादी और गैर-बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के मध्यमान आकार क्रमशः ₹283.87 करोड़ और ₹40.30 करोड़ पाया गया, जो अनुभवजन्य आंकड़ों के ही समान है।

सारणी बी3 : भौगोलिक स्थिति आधारित परियोजना लागत-आकार की विवरणात्मक सांख्यिकी

सांख्यिकी	बहु-राज्यीय	एकल राज्यीय
परियोजनाओं की संख्या	72	2040
माध्य	1001.80	309.30
मानक विचलन	1284.20	853.89
माध्यिका	396.22	65.44
स्क्यूनेस	2.43	8.61
कर्टोसिस	10.99	108.82
3-मानक लॉगनॉर्मल की फिटिंग		
γ	12.2740	9.9044
μ	5.9003	4.0432
σ	1.7007	1.9293

सारणी बी4 : इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन- इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित परियोजना लागत-आकार की विवरणात्मक सांख्यिकी

सांख्यिकी	बहु-राज्यीय	एकल राज्यीय
परियोजनाओं की संख्या	661	1451
माध्य	622.14	201.15
मानक विचलन	1084.00	733.93
माध्यिका	283.87	40.30
स्क्यूनेस	5.66	11.02
कर्टोसिस	52.25	167.65
3-मानक लॉगनॉर्मल की फिटिंग		
γ	5.3906	9.8992
μ	5.4444	3.5443
σ	1.5423	1.7773

उद्योग-वार देखें तो, बुनियादी ढांचा क्षेत्र जिसमें (i) बिजली, (ii) दूरसंचार, (iii) बंदरगाह और हवाई अड्डे, (iv) भंडारण और जल प्रबंधन, (v) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), औद्योगिक, बायोटेक और आईटी पार्क, (vi) सड़क और पुल शामिल हैं, जिसकी हिस्सेदारी 2017-18 में 51.8 प्रतिशत थी, वह 2018-19 में बढ़कर 58.5 प्रतिशत हो गयी यद्यपि इसके सबसे बड़े घटक, अर्थात, 'ऊर्जा क्षेत्र' की हिस्सेदारी में भारी गिरावट हुई थी।

बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत के मामले में 'पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स' क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गयी। वर्ष 2018-19 में स्वीकृत 5 परियोजनाओं में से चार 'नई' थीं और एक 'विस्तार और आधुनिकीकरण' के लिए थी।

चार्ट 1 : बैंकों/एफआई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में प्रमुख उद्योगों की हिस्सेदारी

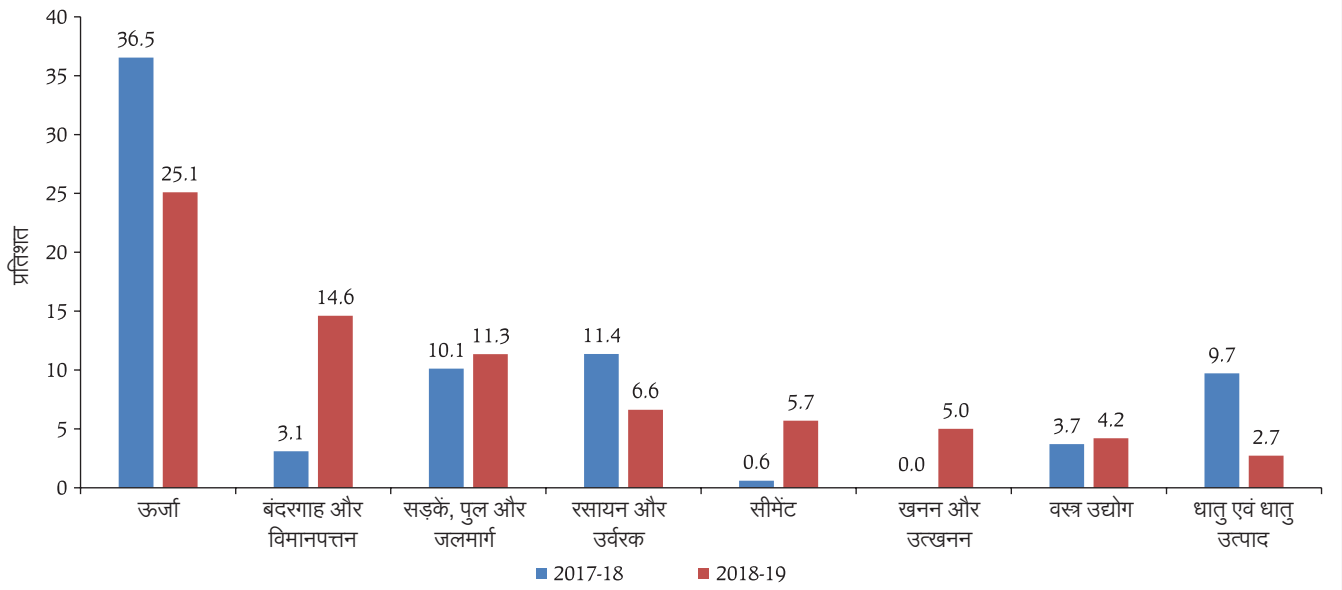

कुल परियोजना लागत में सीमेंट 'परियोजनाओं की हिस्सेदारी में 2017-18 की मामूली 0.6 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2018-19 में 5.7 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई और इससे आगामी वर्षों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विस्तार को बल मिल सकता है। "सीमेंट" उद्योग में कुल परियोजना लागत (और परियोजनाओं की संख्या) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह 2017-18 के ₹1,068 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹10,138 करोड़ हो गई (संख्या क्रमशः तीन से बढ़कर ग्यारह परियोजनाएं)। वर्ष 2018-19 में स्वीकृत इन ग्यारह परियोजनाओं में से आठ 'नई' थीं और तीन 'विस्तार और आधुनिकीकरण' के लिए थीं। हालांकि, उद्योग समूह जैसे धातु और धातु उत्पाद और विनिर्माण क्षेत्र में 2018-19 के दौरान मंदी रही जैसा कि कुल परियोजना लागत के साथ-साथ परियोजनाओं की संख्या में भी आयी भारी गिरावट से प्रकट हुआ और इसका विपरीत प्रभाव कुछ समय तक पड़ने की संभावना है। अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों में, जहाँ 'खनन और उत्खनन' की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, 'रासायनिक और रासायनिक उत्पादों की हिस्सेदारी में कमी आयी। 'खनन और उत्खनन' क्षेत्र की सकल परियोजना लागत और साथ ही परियोजनाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई और चार 'नई' परियोजनाओं के साथ दो अन्य परियोजनाओं का 'विस्तार और 'आधुनिकीकरण' किया गया। (चार्ट 1 और अनुबंध: सारणी ए7)

किसी परियोजना के लिए निर्णायक कारक होते हैं- परियोजना का स्थान, कच्चे माल की सुलभता, कुशल श्रम की उपलब्धता, पर्याप्त आधारभूत संरचना, बाजार का आकार और विकास की संभावनाएं। पिछले पांच वर्षों (2014-15 से 2018-19) के आंकड़ों से पता चला है कि 56 प्रतिशत परियोजनाएं इन छह राज्यों में थीं- आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में थीं, जिससे अन्य राज्यों की तुलना में उनकी अधिक लाभप्रद भौगोलिक स्थिति का संकेत मिलता है (चार्ट 2 ए)।

चार्ट 2 ए : 2014-15 से 2018-19 की अवधि में स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण*

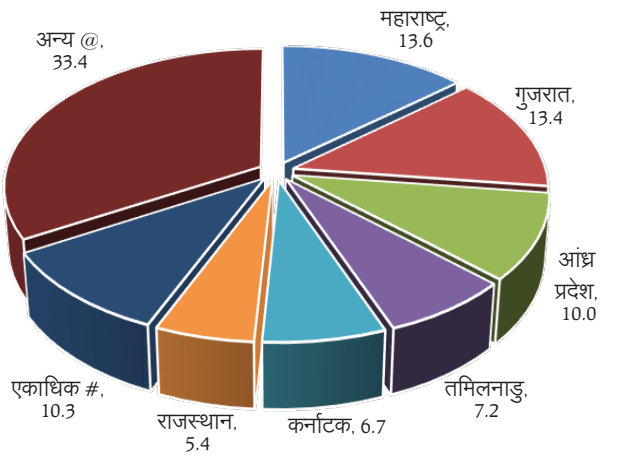

#: 'एकाधिक राज्यों' में चल रही परियोजनाएं।
* : हिस्सेदारी प्रतिशत में दी गयी है।
@: इसमें वेराज्य शामिल हैं जिनकी हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से कम है।

चार्ट 2 बी : 2009-10 से 2013-14 की अवधि में स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण*

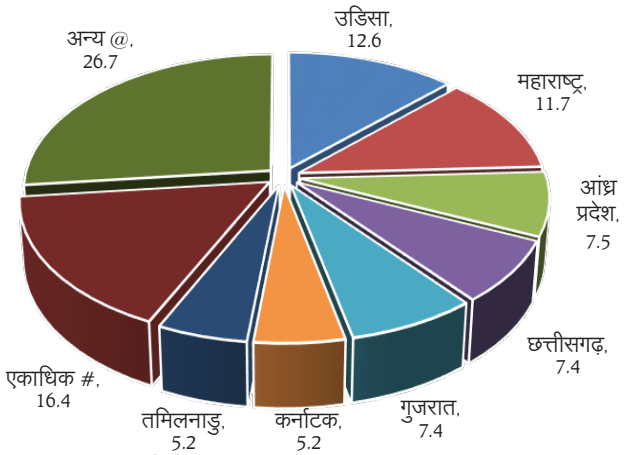

#: 'एकाधिक राज्यों' में चल रही परियोजनाएं।
* : हिस्सेदारी प्रतिशत में दी गयी है।
@: इसमें वे राज्य शामिल हैं जिनकी हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से कम है।

2009-14 की पंचवर्षीय अवधि की तुलना में 2014-19 की पंचवर्षीय अवधि में एक से अधिक राज्यों को शामिल करने वाली परियोजनाओं के प्रसार में काफी गिरावट आई है। यह आंशिक रूप से इस कारण है कि कुल मेगा परियोजनाओं में बहु-राज्य मेगा परियोजनाओं (कुल ₹5,000 करोड़ और अधिक की परियोजना लागत वाली) की हिस्सेदारी कम है। 2014-19 के दौरान स्वीकृत कुल 15 मेगा परियोजनाओं में से केवल एक (6.67 प्रतिशत) बहुराज्यीय थी जबकि 2009-14 की अवधि में कुल 63 मेगा परियोजनाएं स्वीकृत हुई थीं जिनमें से 09 (14.29 प्रतिशत) ऐसी थीं जो एक से अधिक राज्यों में फैली थीं (चार्ट 2 ए और चार्ट 2 बी)।

2018-19 के दौरान बैंकों / एफआई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में सबसे अधिक हिस्सेदारी (11.8 प्रतिशत) आंध्र प्रदेश की थी जिसके बाद क्रमश: तमिलनाडु (11.5 प्रतिशत), महाराष्ट्र (10.9 प्रतिशत), गुजरात (9.9 प्रतिशत), तेलंगाना (8.2 प्रतिशत), राजस्थान (6.8 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (6.2 प्रतिशत) का स्थान है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों की हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम हुई। वहीं दूसरी ओर तेलंगाना की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिसके बाद तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का स्थान रहा (चार्ट 3 और अनुबंध: सारणी ए 8)।

IV. निवेश इरादों का चरणबद्ध विन्यास

विभिन्न वर्षों के दौरान स्वीकृत अनेक परियोजनाओं में परिकल्पित कैपेक्स के चरणबद्ध प्रोफाइल की जानकारी से कैपेक्स के अल्पकालिक (एक वर्ष) पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। 2018-19 में बैंकों / एफआई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के समूह में चरणबद्धता संकेत करती है कि कुल प्रस्तावित व्यय का लगभग 35 प्रतिशत (₹62,561 करोड़) वर्ष 2018-19 में, 30 प्रतिशत (₹53,351 करोड़) 2019-20 में और 24 प्रतिशत (₹42,281 करोड़) बाद के वर्षों में खर्च किया जाएगा।

चार्ट 3 : बैंकों/एफआई द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में प्रमुख राज्यों की हिस्सेदारी

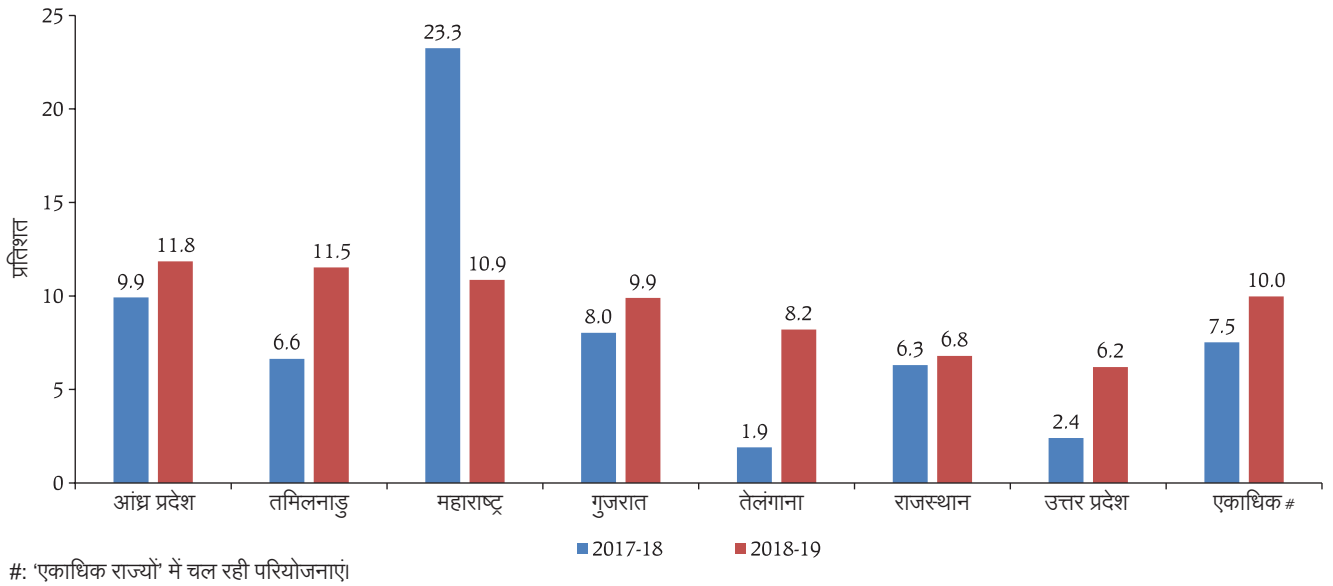

#: 'एकाधिक राज्यों' में चल रही परियोजनाएं।

वर्ष 2018-19 में स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत का लगभग 11 प्रतिशत 2015-16 से 2017-18 के दौरान पहले ही खर्च किया जा चुका है (अनुबंध: सारणी ए1)।

नियोजित व्यय में से, 2018-19 में परिकल्पित कुल कैपेक्स में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई हालांकि बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूरियों में कमी आयी थी। वर्ष 2018-19 में, अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजारों के माध्यम से उठाए गए संसाधनों से होने वाले कैपेक्स में तीव्र वृद्धि हुई और यह एक साल पहले के अपने स्तर से लगभग 133 प्रतिशत हो गया। 2018-19 में पूंजी बाजार (इक्विटी रूट) ने ₹1,179 करोड़ के परिकल्पित कैपेक्स का वित्तपोषण किया जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम था (अनुबंध: सारणी ए1, ए2, ए3)।

संक्षेप में, यह आकलन किया जाता है कि वर्ष 2018-19 के दौरान निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा सभी माध्यमों से कुल मिलाकर ₹1,96,312 करोड़ (जिसमें से ₹1,11,710 करोड़ वर्ष के दौरान प्रदान की गयी नई मंजूरियाँ थीं) कैपेक्स व्यय होगा जिसका मतलब होगा लगभग 24 प्रतिशत का भारी सुधार। इस सुधार का प्रमुख श्रेय कैपेक्स वित्तपोषण के ईसीबी माध्यम को दिया जा सकता है। चैनल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इतना ही नहीं, 2019-20 में पाइपलाइन में पड़ी परियोजनाओं पर आधारित नियोजित कैपेक्स भी ₹1,20,157 करोड़ के उच्च स्तर पर रहने के पूरे आसार हैं जो पिछले वर्ष (₹84,602करोड़) की तुलना में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है (अनुलग्नक: सारणी ए2, ए4)।

आगे बढ़ते हुए, 2019-20 में संयुक्त रूप से परिकल्पित कैपेक्स 2019-20 में स्वीकृत होने वाली परियोजनाओं के नए समूह द्वारा 2019-20 में किए जाने वाले कॉर्पोरेट निवेश के स्तर पर भी निर्भर करेगा। वित्तपोषण के प्रमुख चैनलों से परिकल्पित कैपेक्स और अधिक बढ़ने की संभावना है क्योंकि स्वीकृत / अनुबंधित राशि 2018-19 की पहली छमाही की तुलना में 2019-20 की पहली छमाही में अधिक रहेगी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत कुल परियोजना लागत में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ और यह ₹86,607 करोड़ से बढ़कर ₹1,25,305 करोड़ हो गई। ईसीबी के माध्यम से कैपेक्स उद्देश्य के लिए अनुबंधित कुल ऋण राशि ₹39,833 करोड़ से बढ़कर ₹61,833 करोड़ हो गई (सारणी 1)।

[3] पाइपलाइन प्रोजेक्ट ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका कार्यान्वयन प्रारंभ हो चुका है। किसी पाइपलाइन प्रोजेक्ट से कैपेक्स किसी वर्ष के लिए वे परिकल्पित राशियाँ हैं जो उस वर्ष के पहले वाले वर्ष में मंजूर हो चुकी हैं।

सारणी 1 : बैंकों/एफ आई/ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी/ आईपीओ के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाएं*

	छमा.1 : 2019-20		छमा.1 : 2018-19	
	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत / अनुबंधित राशि (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत / अनुबंधित राशि (₹ करोड़ में)
बैंकों/एफ आई ईसीबी/एफसीसीबी/	142	1,25,305	193	86,607
आरडीबी	272	61,833	262	39,833
आईपीओ	9	78	30	481
कुल	**423**	**1,87,216**	**485**	**1,26,921**

*अनंतिम आंकड़े

V. निजी स्थाननऔर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा वित्तपोषित कॉर्पोरेट निवेश

हाल के वर्षों में, बॉन्ड और डिबेंचर जैसे कर्ज के लिखत तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) कैपेक्स वित्तपोषण के प्रमुख वैकल्पिक स्रोत बनकर उभरे हैं। वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान कर्ज के निजी स्थानन (बॉन्ड और डिबेंचर) के माध्यम से निधि संग्रह में बड़ी वृद्धि देखने को मिली परंतु 2017-18 और 2018-19 के दौरान इसमें कमी आयी। कैपेक्स वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोत के रूप में एफडीआई के लिए वरीयता भी देखने को मिली जिसमें 2012-13 से 2016-17 तक एफडीआई राशि में वृद्धि हुई। इसके बाद, यह 2017-18 में इसमें गिरावट आयी परंतु 2018-19 में फिर से यह बढ़ गया। 2019-20 की पहली छमाही में एफडीआई प्रवाह में वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जारी रही (सारणी 2)।

सारणी 2 : निजी स्थानन और एफडीआई (₹ करोड़ में)

अवधि	कर्ज- निजी स्थानन*	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश**
2011-12	27,040	1,65,146
2012-13	59,188	1,21,907
2013-14	56,042	1,47,518
2014-15	97,358	1,81,682
2015-16	1,17,394	2,62,322
2016-17#	1,53,136	2,91,696
2017-18#	1,35,988	2,88,889
2018-19#	1,34,540	3,09,867
छमा.1:2019-20#	51,068	1,82,000
(छमा.1:2018-19)#	(55,022)	(1,55,117)

*: केवल निजी क्षेत्र की विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की कंपनियों के लिए
**: आवक एफडीआई में केवल इक्विटी पूंजी शामिल है
#: अनंतिम आंकड़े
स्रोत : प्राइम डेटाबेस और भारत सरकार।

VI. निष्कर्ष

यह लेख 2019-20 में निवेश गतिविधियों भावी परिदृश्य के आकलन के लिए फर्मों के निवेश इरादों से जुड़े डेटा का उपयोग करता है। स्वीकृत / अनुबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के चरणबद्ध विन्यास से निकट भविष्य में किए जाने वाले संभावित निवेश के आकलन में सहायता मिलती है। यह लेख परियोजना लागत के वितरण में काफी बड़ी राइट टेल की मौजूदगी को दर्शाता है। इसमें यह पाया गया है कि परियोजना लागत डेटा में इस सकारात्मक विषमता को लॉगनार्मल वितरण से समुचित रूप से समझा जा सकता है और इसलिए यह इस विषय से संबंधित आगे के शोध-कार्य में उपयोगी हो सकता है।

किसी वर्ष विशेष के दौरान स्वीकृत / अनुबंधित उच्च मूल्य और मेगा परियोजनाएं सभी परियोजनाओं के समूह के चरणबद्ध विन्यास को प्रभावित करती हैं। वर्ष 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव के चलते वर्ष 2011-12 के बाद से बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत नई मेगा परियोजनाओं की संख्या कम रही है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि वैश्विक वित्तीय संकट से पहले या उसके आसपास जिन परियोजनाओं की घोषणा और क्रियान्वयन किया जा चुका था, उन्हें अपनी स्वीकृत निवेश योजनाओं को निष्पादित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय पूंजी मिली।

वर्ष 2019-20 में पहले के सभी वर्षों में स्वीकृत पाइपलाइन परियोजनाओं के आधार पर सभी स्रोतों से नियोजित या परिकल्पित कैपेक्स में उल्लेखनीय सुधार के संकेत मिलते हैं। अल्प से मध्यम अवधि में निवेश-चक्र के गति पकड़ने के आसार हैं लेकिन यह तेजी कब तक बनी रहेगी, इस पर बारीकी से नज़र रखने की जरूरत है।

संदर्भ

Abberger, K (2005), "The Use of Qualitative Business Tendency Surveys for Forecasting Business Investment in Germany", *ifo Working Paper No.* 13, June

Aurizio, L. D. and Stefano, I. (2011), "Investment Forecasting with Business Survey Data", *Working Paper Number* 832, November, Bank of Italy.

Barnes, S. and Ellis, C. (2005), "Indicators of short-term Movements in Business Investment", *Bank of England, Quarterly Bulletin, Spring,* 30-38.

Ferrari, N (2005), "Forecasting corporate investment-An indicator based on revisions in the French Investment survey", *DESE Working Paper, October.*

Osterholm, P. (2013), "Forecasting Business Investment in the Short Term Using Survey Data", *Working Paper, Number* 131, November, National Institute of Economic Research.

Rangarajan, C. (1970), "Forecasting Capital Expenditure in the Corporate Sector", *Economic and Political Weekly, December* 19.

Reserve Bank of India: Various data releases and other publications.

अनुबंध

सारणी ए1: बैंकों/एफआई द्वारा मंजूर परियोजनाओं के कैपेक्स की चरणबद्धता

मंजूरी का वर्ष ↓	परियोजनाओं की संख्या	मंजूरी के वर्ष में परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	संशोधन/ निरसन@ के कारण परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20 के बाद
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2010-11 तक				3,13,583	2,23,698	1,23,259	58,668	11,938	118	869				
2011-12	636	2,12,002	1,91,592 (9.6)	23,005	66,915	55,384	28,190	9,470	2,926					
2012-13	414	1,96,345	1,89,483 (3.5)	82	36,664	56,725	48,976	27,325	11,219	6,447	2,045			
2013-14	472	1,34,019	1,27,328 (5.0)		1,332	15,139	34,769	44,925	19,909	7,105	2,677	1,472		
2014-15	326	87,601	87,253 (0.4)			98	14,822	34,589	25,765	9,535	1,246	162	1,036	
2015-16	346	95,371	91,781 (3.8)				3,787	7,434	37,517	28,628	8,079	4,964	1,152	220
2016-17	541	1,82,807	1,79,249 (2.0)				1,352	3,952	25,388	71,186	41,075	21,643	8,566	6,087
2017-18	485	1,72,831	1,68,239 (2.6)					620	15,184	12,445	63,001	41,436	22,767	12,786
2018-19	414	1,76,581							569	6,847	10,972	62,561	53,351	42,281
कुल#				**3,36,670**	**3,28,609**	**2,50,605**	**1,90,564**	**1,40,253**	**1,38,595**	**1,43,062**	**1,29,095**	**1,32,238**	**86,872**	**61,374**
प्रतिशत परिवर्तन					**-2.4**	**-23.7**	**-24.0**	**-26.4**	**-1.2**	**3.2**	**-9.8**	**2.4**	*	

#: कॉलमों के योग किसी वर्ष विशेष में परिकल्पित पूंजीगत व्यय को दर्शाते हैं जिसमें उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिन्हें अलग-अलग वर्षों में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। ये प्रत्याशित अनुमान हैं, जिसमें सिर्फ परिकल्पित निवेश को शामिल किया गया है। ये वास्तव में प्राप्त / प्रयुक्त अनुमान से भिन्न हैं।

*: 2019-20 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2019-20 में जिन पूंजीगत व्यय के प्रस्ता वों को मंजूर किए जाने की संभावना है, वे उपलब्ध नहीं हैं।

@: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े निरसन का प्रतिशत हैं।

सारणी ए2: ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी** द्वारा निधि प्राप्त परियोजनाओं* के कैपेक्स की चरणबद्धता

ऋणों का अनुबंध वर्ष ↓	कंपनियों की संख्या	कुल अनुबंधति ऋण (₹ करोड़ में)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20 के बाद
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2010-11 तक			31,829	13,130	2,873	500							
2011-12	438	40,012		25,212	12,800	1,900	100						
2012-13	519	65,692			37,792	20,267	6,300	1,333					
2013-14	563	80,736				56,197	20,976	3,563					
2014-15	478	57,327					36,791	16,806	3,151	575	2	2	
2015-16	314	38,885						28,998	7,311	2,572	4		
2016-17	346	22,154							14,953	6,005	1,192	2	2
2017-18	419	37,896								17,822	13,054	6,484	536
2018-19	535	76,515									48,643	25,706	2,166
कुल&			**31,829**	**38,342**	**53,465**	**78,864**	**64,167**	**50,700**	**25,415**	**26,974**	**62,895**	**32,194**	**2,704**
प्रतिशत परिवर्तन				**20.5**	**39.4**	**47.5**	**-18.6**	**-21.0**	**-49.9**	**6.1**	**133.2**	**#**	

*: वे परियोजनाएं जिन्हें बैंकों / वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त नहीं हुई।

**: रुपये में अंकित बॉण्ड (आरडीबी) 2016-17 से शामिल किए गए।

#: 2019-20 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2018-19 में जिन पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की संभावना है, वे उपलब्ध नहीं हैं।

&: अनुमान प्रत्याशित हैं, इनमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल किए गए हैं। ये वास्तव में प्राप्त / प्रयुक्त अनुमानों से भिन्न हैं।

सारणी ए3: इक्विटी निर्गमों* द्वारा निधि प्राप्त परियोजनाओं के कैपेक्स की चरणबद्धता

इक्विटी निर्गम की अवधि ↓	कंपनियों की संख्या	परिकल्पित कैपेक्स (₹ करोड़ में)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20 के बाद
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2010-11 तक			1,923	726	95								
2011-12	21	973	153	460	360								
2012-13	25	1,135			533	494	108						
2013-14	21	454					384	70					
2014-15	24	1,078					189	557	332				
2015-16	40	4,511					11	644	2,753	849	183	71	
2016-17	29	1,159						14	471	368	163	143	
2017-18	51	1,538								419	327	787	5
2018-19	39	609									506	90	13
कुल&			**2,076**	**1,186**	**988**	**494**	**692**	**1,285**	**3,556**	**1,636**	**1,179**	**1,091**	**18**
प्रतिशत परिवर्तन				**-42.9**	**-16.7**	**-50.0**	**40.0**	**85.7**	**176.9**	**-54.0**	**-27.9**	**#**	

*: वे परियोजनाएं जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ एफसीसीबी/आरडीबी से सहायता प्राप्त नहीं हुई थी।

#: 2019-20 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2019-20 में जिन पूंजीगत व्यय के प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की संभावना है वे उपलब्ध नहीं हैं।

&: ये प्रत्याशित अनुमान हैं जिसमें सिर्फ परिकल्पित निवेश को शामिल किया गया है। ये वास्तव में प्राप्त/प्रयुक्त अनुमान से भिन्न हैं।

सारणी ए4: बैंकों/एफआई/आईपीओ/ ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी* द्वारा निधि प्राप्त परियोजनाओं के कैपेक्स की चरणबद्धता

मंजूरी का वर्ष ↓	कंपनियों की संख्या	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20 के बाद
	बैंक/एफआई/ ईसीबी/ एफसीसीबी/ आरडीबी/ आईपीओ												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2010-11 तक			3,47,335	2,37,554	1,26,227	59,168	11,938	118	869	0	-	-	-
2011-12	1,095	2,32,577	23,158	92,587	68,544	30,090	9,570	2,926	-	-	-	-	-
2012-13	958	2,56,310	84	36,664	95,050	69,737	33,733	12,552	6,447	2,045	-	-	-
2013-14	1,056	2,08,518	-	1,332	15,139	90,966	66,285	23,542	7,105	2,677	1,472	-	-
2014-15	828	1,45,658	-	-	98	14,822	71,569	43,128	13,018	1,821	164	1,038	-
2015-16	700	1,35,177	-	-	-	3,787	7,445	67,159	38,692	11,500	5,151	1,223	220
2016-17	916	2,02,562	-	-	-	1,352	3,952	25,402	86,610	47,448	22,998	8,711	6,089
2017-18	955	2,07,673	-	-	-	-	620	15,184	12,445	81,242	54,817	30,038	13,327
2018-19	988	2,53,705	-	-	-	-	-	569	6,847	10,972	1,11,710	79,147	44,460
कुल&			**3,70,577**	**3,68,145**	**3,05,058**	**2,69,922**	**2,05,112**	**1,90,580**	**1,71,164**	**1,57,705**	**1,96,312**	**1,20,157**	**64,096**
प्रतिशत परिवर्तन				**-0.7**	**-17.1**	**-11.5**	**-24.0**	**-7.1**	**-10.2**	**-7.9**	**24.5**	**#**	

*: 2016-17 से रुपये में अंकित बॉन्ड (आरडीबी) शामिल किए गए हैं।

#: 2019-20 के लिए प्रतिशत परिवर्तन की गणना नहीं की गई है क्योंकि 2019-20 तक स्वीकृति कीसंभावनाओं वाली परियोजनाओं से संबंधित पूंजीगत व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

&: आकलन प्रत्याशित है, जिसमें सिर्फ परिकल्पित निवेश शामिल हैं। यह वास्तव में प्राप्त/प्रयुक्त आंकड़ों से भिन्न है।

सारणी ए5: बैंकों / एफआई द्वारा मंजूर परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण : 2009-10 से 2018-19

अवधि		₹100 करोड़ से कम	₹100 करोड़ से ₹500 करोड़ तक	₹500 करोड़ से ₹1000 करोड़ तक	₹1000 करोड़ से ₹5000 करोड़ तक	₹5000 करोड़ और उससे अधिक	कुल
2009-10	परियोजनाओं की संख्या	439	189	40	39	22	**729**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	3.8	11.0	6.8	20.8	57.5	**100 (4,09,502)**
2010-11	परियोजनाओं की संख्या	412	172	42	51	20	**697**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	4.4	10.2	8.6	29.3	47.5	**100 (3,75,176)**
2011-12	परियोजनाओं की संख्या	420	145	36	26	9	**636**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	8.3	17.0	13.7	27.6	33.4	**100 (1,91,592)**
2012-13	परियोजनाओं की संख्या	245	119	20	23	7	**414**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	4.8	14.6	7.3	26.8	46.4	**100 (1,89,483)**
2013-14	परियोजनाओं की संख्या	306	115	25	21	5	**472**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	8.3	20.0	13.9	29.1	28.7	**100 (1,27,328)**
2014-15	परियोजनाओं की संख्या	223	65	18	19	1	**326**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	9.0	16.6	14.6	47.8	12.0	**100 (87,253)**
2015-16	परियोजनाओं की संख्या	214	76	34	21	1	**346**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	8.6	20.9	26.0	38.5	5.9	**100 (91,781)**
2016-17	परियोजनाओं की संख्या	287	180	29	40	5	**541**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	5.8	23.3	11.9	41.7	17.4	**100 (1,79,249)**
2017-18	परियोजनाओं की संख्या	263	149	28	42	3	**485**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	5.2	21.0	10.8	43.9	19.1	**100 (1,68,239)**
2018-19	परियोजनाओं की संख्या	215	115	39	40	5	**414**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	4.3	15.8	15.3	41.1	23.5	**100 (1,76,581)**

नोट : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े ₹ करोड़ में परियोजनाओं की कुल लागत दर्शाते हैं।

2. प्रतिशत हिस्सेदारी परियोजना की कुल लागत का प्रतिशत है।

सारणी ए6: बैंकों / एफआई द्वारा मंजूर परियोजनाओं का उद्देश्य-वार वितरण : 2010-11 से 2018-19

अवधि	परियोजनाओं की संख्या और हिस्सेदारी	नई	विस्तार और आधुनिकीकरण	विविधीकरण	अन्य	कुल
2010-11	परियोजनाओं की संख्या	454	224	6	13	**697**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	66.8	30.9	1.8	0.5	**100 (3,75,176)**
2011-12	परियोजनाओं की संख्या	449	172	5	10	**636**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	70.6	23.1	0.1	6.3	**100 (1,91,592)**
2012-13	परियोजनाओं की संख्या	303	107	-	4	**414**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	84.2	14.7	-	1.1	**100 (1,89,483)**
2013-14	परियोजनाओं की संख्या	361	95	2	14	**472**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	65.2	20.1	-	14.7	**100 (1,27,328)**
2014-15	परियोजनाओं की संख्या	203	92	2	29	**326**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	39.4	14.7	0.2	45.7	**100 (87,253)**
2015-16	परियोजनाओं की संख्या	260	64	3	19	**346**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	73.6	14.3	0.1	12.0	**100 (91,781)**
2016-17	परियोजनाओं की संख्या	429	97	4	11	**541**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	78.6	9.9	0.1	11.3	**100 (1,79,249)**
2017-18	परियोजनाओं की संख्या	396	80	2	7	**485**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	89.0	9.4	0.1	1.5	**100 (1,68,239)**
2018-19	परियोजनाओं की संख्या	320	78	-	16	**414**
	प्रतिशत हिस्सेदारी	76.9	19.7	-	3.4	**100 (1,76,581)**

नोट : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े ₹ करोड़ में परियोजनाओं की कुल लागत दर्शाते हैं।

2. प्रतिशत हिस्सेदारी परियोजना की कुल लागत का प्रतिशत है।

3. -: शून्य / नगण्य।

सारणी ए7: बैंकों / एफआई द्वारा मंजूर परियोजनाओं का उद्योगवार वितरण : 2009-10 से 2018-19

उद्योग	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी
इन्फ्रास्ट्रक्चर	100	48.9	121	53.7	107	47.4	82	47.9	87	39.8	74	48.8	108	72.0	204	62.6	150	51.8	125	58.5
i) बिजली	75	30.7	105	46.3	82	42.4	71	39.4	70	35.1	65	42.2	92	57.1	170	45.4	117	36.5	81	25.1
ii) दूरसंचार	6	16.4	2	5.7	1	0.0	2	5.6	1	0.0	1	4.9	1	0.3	1	0.0	-	-	-	-
iii) बदरंगाह एव एयरपोर्ट	2	0.3	1	0.7	1	1.3	1	1.9	1	0.8	-	-	3	2.4	8	5.7	6	3.1	5	14.6
iv) भडारण एवं जल प्रबंधन	2	0.9	1	0.0	12	0.5	-	-	5	1.1	2	0.6	4	4.2	6	3.7	2	0.4	15	5.3
v) एसईजेड, औद्योगिक, बायोटेक तथा आई टी पार	15	0.6	12	1.1	11	3.2	8	0.9	8	1.5	3	0.9	1	0.4	2	0.4	9	1.6	6	2.2
vi) सडकें एव पुल	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.2	3	0.3	7	7.6	17	7.3	16	10.1	18	11.3
रसायन एवं कीटनाशक	28	0.8	27	1.3	17	3.5	19	1.1	15	1.0	7	2.6	11	1.6	10	2.1	23	11.4	20	6.6
सीमेंट	29	2.8	15	2.7	9	2.0	11	3.9	12	7.1	7	3.8	5	1.9	5	2.3	3	0.6	11	5.7
खनन और उत्खनन	9	3.4	1	0.2	4	0.2	2	0.1	1	0.6	2	0.1	10	2.7	4	0.4	1	0.0	7	5.0
वस्त्र	77	2.2	77	2.9	94	7.0	31	1.9	58	10.3	50	4.1	49	4.8	57	4.1	54	3.7	29	4.2
धात एवं धातु के उत्पाद	134	18.1	113	21.1	73	16.3	51	28.9	44	17.0	17	17.4	14	1.5	23	4.9	21	9.7	15	2.7
रबड़ उत्पाद	15	0.4	19	0.5	18	0.9	7	0.5	9	0.3	8	0.8	4	0.5	8	0.2	10	2.5	6	2.5
निर्माण	20	11.5	18	3.3	23	1.8	20	2.8	27	2.1	29	4.0	26	1.8	60	12.0	39	5.3	28	2.5
अस्पताल	23	0.9	22	0.6	9	0.3	17	1.4	10	0.7	2	0.1	1	0.0	22	1.1	18	1.8	15	2.3
होटल एवं रेस्तरां	56	2.6	63	3.5	51	4.6	31	3.1	29	2.7	15	1.1	16	1.1	12	0.8	29	2.9	28	1.7
फार्मास्यूटिकल्स	31	0.5	18	0.3	20	0.8	10	0.4	19	1.3	9	1.5	11	0.3	12	1.1	15	0.6	23	1.5
खाद्य पदार्थ	41	0.5	39	0.7	41	1.5	36	0.9	43	1.8	34	2.9	26	1.8	38	0.9	47	2.8	28	1.3
अन्य सेवाएं	2	0.0	3	0.1	4	0.1	2	0.1	8	0.8	2	0.1	-	-	3	0.1	-	-	11	1.2
अन्य विनिर्माण	18	0.5	22	0.2	22	0.4	8	0.1	15	0.7	7	0.1	9	1.4	7	0.2	9	0.7	20	0.7
परिवहन उपकरण	25	1.3	27	0.8	26	2.6	17	0.9	16	1.2	7	5.3	4	2.5	9	3.6	10	0.3	5	0.7
अन्य*	121	5.6	112	8.2	118	10.5	70	5.7	79	12.6	56	7.3	52	6.0	67	3.6	56	5.9	43	3.0
कुल	**729**	**100**	**697**	**100**	**636**	**100**	**414**	**100**	**472**	**100**	**326**	**100**	**346**	**100**	**541**	**100**	**485**	**100**	**414**	**100**
परियोजनाओं की कुल लागत (₹ करोड़)	**4,09,502**		**3,75,176**		**1,91,592**		**1,89,483**		**1,27,328**		**87,253**		**91,781**		**1,79,249**		**1,68,239**		**1,76,581**	

* : इनमें औषधि एव ड्रग्स, कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप, कागज़ एवं कागज़ के उत्पाद, छपाई एवं प्रकाशन, रबड़, आईटी सॉफ्टवेयर, सचार एवं व्यापार सवाएँ, मनोरंजन आदि जैसै उद्योग शामिल हैं।

- : कुछ नहीं/नगण्य

टिप्पणी: प्रतिशत हिस्सेदारी परियोजना की कुल लागत का प्रतिशत है।

सारणी ए8: बैंकों / एफआई द्वारा मंजूर परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण : 2009-10 से 2018-19

राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी	परियोजनाओं की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी
आंध्र प्रदेश	73	7.1	65	11.4	52	5.1	35	5.7	37	4.0	24	8.1	33	12.3	47	8.0	22	9.9	29	11.8
तमिलनाडु	66	5.5	93	6.1	58	5.7	22	1.8	33	5.4	27	2.9	26	9.3	22	4.4	28	6.6	33	11.5
महाराष्ट्र	117	10.0	71	7.4	86	19.1	67	10.7	76	19.7	38	14.8	36	9.4	57	8.8	65	23.3	37	10.9
गुजरात	69	3.2	65	9.6	75	9.0	58	5.6	66	14.5	71	9.5	61	15.1	102	23.0	71	8.0	55	9.9
तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.8	52	6.8	17	1.9	25	8.2
राजस्थान	23	2.9	28	0.8	49	4.9	41	5.3	24	1.4	29	11.1	10	0.9	23	2.8	33	6.3	20	6.8
उत्तर प्रदेश	27	0.4	32	4.6	42	7.8	26	4.4	21	1.1	20	5.4	15	2.3	22	3.7	30	2.4	29	6.2
कर्नाटक	42	1.4	40	7.2	39	12.0	20	1.6	39	6.2	27	5.4	21	6.2	52	6.8	64	9.6	33	4.7
पंजाब	23	0.4	38	1.1	37	1.7	12	10.9	28	1.5	6	0.3	11	1.7	29	2.1	31	2.2	14	1.8
पश्चिम बंगाल	33	2.6	29	3.3	19	4.9	13	1.0	12	1.2	9	1.3	14	3.1	18	1.7	14	1.8	15	1.6
मध्य प्रदेश	23	4.2	21	5.2	16	5.6	13	3.9	30	6.1	14	3.9	21	6.9	18	7.5	10	0.7	11	1.4
ओडिशा	25	13.9	25	7.4	15	6.3	10	26.8	10	11.7	5	15.9	6	3.1	6	3.1	5	3.0	9	1.3
छत्तीसगढ़	23	6.0	31	12.1	11	2.4	9	4.1	16	10.7	8	7.4	8	4.7	15	4.0	7	4.8	5	0.8
जम्मू और कश्मीर	2	0.1	3	0.1	5	0.2	10	0.2	10	5.2	2	0.1	9	0.2	3	0.1	8	2.0	12	0.4
हिमाचल प्रदेश	19	0.6	13	0.8	7	0.5	5	0.3	3	1.8	3	0.1	8	1.4	1	0.0	8	2.3	7	0.3
एकाधिक#	45	29.0	48	16.2	34	4.5	15	7.7	21	6.9	10	9.5	13	13.5	17	11.8	16	7.5	16	10.0
अन्य*	119	12.7	95	6.7	91	10.3	58	10.0	46	2.6	33	4.3	44	6.1	57	5.4	56	7.7	64	12.4
कुल	**729**	**100**	**697**	**100**	**636**	**100**	**414**	**100**	**472**	**100**	**326**	**100**	**346**	**100**	**541**	**100**	**485**	**100**	**414**	**100**
परियोजनाओं की कुल लागत (₹ करोड़ में)	**4,09,502**		**3,75,176**		**1,91,592**		**1,89,483**		**1,27,328**		**87,253**		**91,781**		**1,79,249**		**1,68,239**		**1,76,581**	

#: इसमें वे परियोजनाएं शामिल हैं जो एकाधिक राज्यों में चल रही हैं।

*: इसमें शेष राज्य / संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

‘ -’: सूचना उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी : प्रतिशत हिस्सेदारी परियोजना की कुल लागत का प्रतिशत है।